

मूक पत्रिका

निष्पक्ष, निर्भीक, स्वतंत्र आवाज...

वर्ष – 01

अंक – 345

बेमेतरा, शुक्रवार 01 अगस्त 2025

रायपुर एवं बेमेतरा से प्रकाशित

कुल पेज – 8

मूल्य – 5 रुपये

संक्षिप्त समाचार

नीतीश कुमार ने आशा और ममता कार्यकर्ताओं को दिया तोहफा

पटना। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभी वर्ग के लोगों को रिश्ताने में लगे हुए हैं। उन्होंने आशा और ममता कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी घोषणा की। जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) और भाजपा के गठबंधन वाली सरकार के मुखिया नीतीश ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि अब आशा कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन राशि 1,000 रुपये की जगह 3,000 रुपये दिया जाएगा। ममता कार्यकर्ताओं को प्रति प्रसव 300 रुपये की जगह 600 रुपये मिलेगा। नीतीश ने एक्स पर लिखा, नवंबर 2005 में सरकार बनने के बाद से हमलोगों ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर काम किया। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में आशा और ममता कार्यकर्ताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसे ध्यान में रखते हुए तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण में आशा और ममता कार्यकर्ताओं के अहम योगदान को सम्मान देते हुए उनकी मानदेय राशि में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है।

अलकायदा से जुड़ी 30 वर्षीय सदिध आतंकी महिला बेंगलुरु से गिरफ्तार

बेंगलुरु। गुजरात की आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) ने अलकायदा से जुड़ी एक 30 वर्षीय आतंकी महिला को गिरफ्तार किया है। महिला को पहचान शमा परवीन के रूप में हुई है। महिला अल-कायदा इन द ईंडियन सबकॉन्टिनेंट से जुड़े आतंकी माईइयूल की मुख्य साजिशकर्ता है, उसे गुप्त सूचना के बाद कर्नाटक के बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया है। परवीन पर पूरे माईइयूल को चलाने का आरोप है। वह कर्नाटक से एकन्यूआईएस संचालन का समन्वय करने वाली मुख्य संचालक थी। रिपोर्ट के मुताबिक, परवीन को गिरफ्तार करने से पहले एटीएस 23 जुलाई को 4 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया था। सभी की उम्र 20 से 25 साल के बीच है। इनकी पहचान मोहम्मद फरदीन, सैफुल्लाह कुरैशी, जीशान अली और मोहम्मद फैक के रूप में हुई है।

आंध्र प्रदेश के कोनासीमा में निजी स्कूल के प्रधानाचार्य ने छात्रा का रेप किया

अमरावती। आंध्र प्रदेश के डॉ भीमराव अंबेडकर कोनासीमा जिले में एक चौकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक निजी स्कूल के प्रधानाचार्य जयराजू पर स्कूल की नाबालिग छात्रा का यौन उत्पीड़न करने का आरोप है। छात्रा 3 महीने की गर्भवती हो गई है। छात्रा के माता-पिता ने रायवरम पुलिस स्टेशन में एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई गई है। अधिकारियों ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। प्रधानाचार्य को हिरासत में लेकर पूछताछ हो रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, छात्रा स्कूल में कक्षा 9 की छात्रा है। उसके साथ 4 महीने पहले प्रधानाचार्य ने जबरन रेप किया था।

मुंबई की एनआईए कोर्ट का फैसला

मालेगांव धमाके में साध्वी प्रज्ञा समेत सभी आरोपी बरी हुए.....

नई दिल्ली/ एजेंसी

2008 मालेगांव विस्फोट विशेष एनआईए अदालत ने पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत सभी सातों आरोपियों को बरी किया। 2भाजपा की पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत सभी सात आरोपी अदालत में उपस्थित हुए थे। विशेष एनआईए अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में नाकाम रहा, आरोपी संदेह का लाभ पाने के हकदार। यह घटना महाराष्ट्र के सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील मालेगांव शहर में हुए एक शक्तिशाली विस्फोट के लगभग 17 साल बाद हुई है, जिसमें छह लोग मारे गए थे और 100 से अधिक घायल हो गए थे। भाजपा की पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा कि अदालत द्वारा बरी किया जाना न केवल उनकी, बल्कि हर भाजपा की जीत है। प्रज्ञा ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित समेत सभी सात आरोपी, जिन पर गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और मेजर (सेवानिवृत्त) रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी और समीर कुलकर्णी इस मामले के अन्य आरोपी थे। इस मामले की जाँच करने वाली राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) ने आरोपियों के लिए उचित सजा की माँग की थी। यह विस्फोट 29 सितंबर, 2008 को मालेगांव के एक मुस्लिम बहुल इलाके के एक चौक पर हुआ था। यह रमजान का महीना था, जब मुस्लिम समुदाय रोजा रखता है। ईडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि यह संदेह था कि विस्फोट के पीछे के लोगों ने सांप्रदायिक दरार पैदा करने के लिए, हिंदू नवरात्रि उत्सव से ठीक पहले, मुस्लिम पवित्र मक़ा का समय चुना था। स्थानीय पुलिस से जाँच महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) को सौंप दी गई। हालाँकि यह दावा



आतंकवाद कभी भगवा नहीं था और न ही कभी होगा-फडणवीस

17 साल बाद एनआईए की विशेष अदालत ने पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित सहित सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट के इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारे में बयानबाजी तेज हो गई है। एक तरफजहां तरफ भाजपा नेताओं ने इस फैसले का स्वागत किया। साथ ही ‘भगवा आतंकवाद’ के मुद्दे पर विपक्ष को आड़े हाथ लेना शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस फिर से इस फैसले को चुनौती देने की बात पर जोर दे रही है। आइए जानते हैं कि इस मामले में किसने क्या कहाएनआईए कोर्ट के फैसले के बाद तेज होती सियासत के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।

किया गया था कि विस्फोट के बाद 101 लोग घायल हुए थे, एनआईए अदालत ने फैसला सुनाया कि केवल 95 लोग घायल हुए थे, और यह भी कहा कि कुछ चिकित्सा प्रमाणपत्रों में हेराफेरी की गई थी। फैसला सुनते हुए, विशेष न्यायाधीश ए.के. लाहोटी ने कहा: अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि बम मोटरसाइकिल पर लगाया गया था। यह संभव है कि विस्फोटक उपकरण कहीं और रखा गया हो। इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं है कि आरडीएक्स कश्मीर से लाया गया था या ले

हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता... शाह की दो टूक

भारत में आतंकवाद के ‘पतन’ के कगार पर होने की बात दोहराते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में अपने संबोधन में कहा कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकते। पहलगाम नरसंहार और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान कांग्रेस पर निशाना साधते हुए शाह ने कहा कि कांग्रेस ने कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार इसे वापस लेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की उदार नीतियों और तुष्टिकरण के रवये ने देश में आतंकवाद को पगपग और फलने-फूलने का मौका दिया। सौभाग्य से, अब हमारे पास ऐसा नेतृत्व है जो केवल दस्तावेजों पर निर्भर रहने के बजाय निष्ठापूर्ण कार्यवाई करता है, ब्रह्मोस मिसाइल तैनात करता है।

जाया गया था। जाँच यह पता नहीं लगा सकी कि मोटरसाइकिल किसने खड़ी की थी या वह वहाँ कैसे पहुँची।न्यायाधीश ने आगे कहा घटनास्थल की जाँच के दौरान, विस्फोट स्थल के पास एक महत्वपूर्ण पत्थर जूता नहीं किया जा सका, संभवतः घटना के बाद मची अफ़रा-तफ़री के कारण। घटनास्थल पर फ़िंगरप्रिंट के नमूने एकत्र नहीं किए गए। एकत्र किए गए साक्ष्य संभवतः क्षतिग्रस्त या दूषित हो सकते हैं। हालाँकि बाइक के चैसिस से छेड़छाड़ नहीं की गई थी, लेकिन जाँच के लिए उसे ठीक से ठीक भी नहीं किया गया था।

जम्मू-कश्मीर के पुंछ में एलओसी के पास घुसपैठ की कोशिश

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों ने नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पास घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। सुरक्षा बलों ने 2 पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया है। आतंकियों की अभी पहचान नहीं हुई है। एलओसी के पास संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधि का पता चलने के बाद भारतीय सेना और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने पुंछ के देघवार सेक्टर में तलाशी अभियान चलाया था। इलाके में सतर्कता बढ़ा दी गई है। सेना के अधिकारियों ने बताया कि इलाके में संदिग्ध गतिविधि का पता चलने पर जब तलाशी अभियान चलाया गया तो गोलीबारी शुरू हो गई।

मोदी कैबिनेट का मेगा फैसला

रेलवे का विस्तार, किसानों की आय बढ़ाने को बड़ी सौगात

नई दिल्ली/ एजेंसी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2025-26 से 2028-29 तक 4 साल की अवधि के लिए 2000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ केंद्रीय क्षेत्र योजना ‘राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को अनुदान सहायता’ की मंजूरी दी है। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के इस फैसले की जानकारी दी है। सरकार की ओर से बताया गया है कि वर्ष 2025-26 से 2028-29 तक 4 वर्षों की अवधि के लिए अनुदान सहायता पर 2000 करोड़ रुपये का परिव्यय किया जाएगा। एनसीडीसी चार वर्षों की अवधि में खुले बाजार से 20,000 करोड़ रुपये जुटा सकेगी। एनसीडीसी की ओर से नई परियोजनाओं की स्थापना/संयंत्रों के विस्तार, सहकारी समितियों को ऋण देने

और कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण देने हेतु निधियों का उपयोग किया जाएगा। सरकार ने बताया है कि इस कदम से देश भर में डेयरी, पशुधन, मत्स्य पालन, चीनी, कपड़ा, खाद्य प्रसंस्करण, भंडारण और कोल्ड स्टोरेज जैसे विभिन्न क्षेत्रों की 13,288 सहकारी समितियों के 2.9 करोड़ सदस्यों; श्रम और महिलाओं के नेतृत्व वाली सहकारी समितियों को लाभ मिलेगा। वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) की चार वर्षों के लिए 2,000 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता को मंजूरी दी है। इस कदम से संगठन को ऋण देने के लिए अधिक धन जुटाने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति



की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया। सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संवाददाताओं को बताया, एक अच्छे वित्तीय मॉडल को और अधिक समर्थन देने के लिए, मंत्रिमंडल ने एनसीडीसी के लिए चार वर्षों के लिए 2,000 करोड़ रुपये की पूंजी अनुदान

सहायता को मंजूरी दी। एनसीडीसी 8.25 लाख से अधिक सहकारी समितियों को ऋण देता है, जिनके 29 करोड़ सदस्य हैं। कुल सदस्यों में से 94 प्रतिशत किसान समर्थन देने के लिए, मंत्रिमंडल ने एनसीडीसी के लिए चार वर्षों के लिए 20,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त जुटाने में

सक्षम हो सकेगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में एनसीडीसी की ऋण वसूली दर 99.8 प्रतिशत है और एनपीए शून्य है।केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए इटारसी-नागपुर के बीच चौथी रेलवे लाइन की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटारसी और नागपुर के बीच चौथी लाइन को मंजूरी दे दी है। इसका निर्माण दिल्ली और चेन्नई के साथ-साथ मुंबई और हावड़ा को जोड़ने वाले उच्च-घनत्व वाले गलियारे पर किया जाएगा। यह चारों दिशाओं का मिलन बिंदु है। सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, कैबिनेट ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा और झारखंड राज्यों के 13 जिलों को कवर करने वाली चार मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

अलुआबाड़ी से न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे लाइन का होगा विस्तार

कैबिनेट ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए अश्विनी वैष्णव ने बताया कि अलुआबाड़ी से न्यू जलपाईगुड़ी तक रेलवे लाइन के विस्तार पर भी बात की। उन्होंने कहा, अगला काम अलुआबाड़ी और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच 57 किलोमीटर लंबी तीसरी और चौथी रेलवे लाइन का विस्तार है। यह पूर्वांतर की कनेक्टिविटी के लिए बेहद जरूरी है... अलुआबाड़ी बिहार से बंगाल के सिलीगुड़ी तक फैला है। इन लाइनों को मजबूत करना बेहद जरूरी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने छत्रपति संभाजी नगर से परभणी तक रेलवे लाइन के दोहरीकरण की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा, मराठवाड़ा कनेक्टिविटी के लिहाज से यह परियोजना बेहद महत्वपूर्ण है।

डिट्टी सीएम ने चीनी ई-कॉमर्स कंपनी से माफी की मांग की

भगवान जगन्नाथ की छवि वाले पायदान बेचने पर मचा बवाल

भुवनेश्वर/ एजेंसी

ओडिशा में उस वक्त बड़ा विवाद खड़ा हो गया, जब पता चला कि चीनी ई-कॉमर्स वेबसाइट अलीएक्सप्रेस भगवान जगन्नाथ की तस्वीर वाले पायदान बेच रही है। राज्य की उप मुख्यमंत्री पार्वती परिदा ने इस कृत्य को ‘अपमानजनक’ बताया और अलीएक्सप्रेस से माफी की मांग की। उन्होंने एक्स पर उन्होंने लिखा- महारथु जगन्नाथ हर ओडिया के दिल और आत्मा से जुड़े हैं। मैं चीनी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अली एक्सप्रेस द्वारा भगवान जगन्नाथ की तस्वीर वाले पायदान बेचने की कड़ी निंदा करती हूं। इसे तुरंत हटाय जाए



और भक्तों से माफी मांगी जाए। इसके बाद अलीएक्सप्रेस ने कांग्रेस विधायक सोफिया फ़िदीस की पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उसने वह उत्पाद हटा दिया गया है। अलीएक्सप्रेस ने लिखा - हम आपकी रिपोर्ट की सराहना करते हैं। इस उत्पाद की समीक्षा की गई है और इसे हटा दिया गया है। आपके सुझावों से हमें अपने प्लेटफॉर्म को बेहतर

बनाने में मदद मिलती है। धन्यवाद कि आपने हमें एक सुरक्षित और सम्मानजनक ऑनलाइन अनुभव बनाने में सहयोग दिया। फ़िदीस ने अपनी पोस्ट में कहा- भगवान जगन्नाथ की पवित्र तस्वीर वाले पायदान को अली एक्सप्रेस पर बेचने का यह कृत्य घोर निंदनीय है। यह करोड़ों भक्तों की धार्मिक भावनाओं पर सीधा हमला है। तुरंत कार्रवाई हो और सार्वजनिक माफी मांगी जाए। प्रसिद्ध रेत कलाकार और पद्मश्री पुरस्कार विजेता सुदर्शन पटनायक ने भी इस घटना की निंदा की। उन्होंने लिखा- जय जगन्नाथ। हम दुनियाभर के सभी भक्तों से अपील करते हैं कि इस अस्वीकार्य कृत्य के खिलाफ आवाज उठाए।

तेजस्वी की बड़ी टेंशन

मुकेश सहनी ने 60 सीटों पर ठोका दावा

नई दिल्ली। विकासशील ईसान पार्टी (वीआईपी) के प्रमुख मुकेश सहनी ने एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घोषणा करते हुए घोषणा की कि उनकी पार्टी आगामी 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए की गई इस घोषणा ने राज्य के गतिशील राजनीतिक परिदृश्य में नई अटकलों और रणनीतिक पुनर्गणनाओं को हवा दे दी है। पोस्ट में कहा गया है कि वीआईपी 2025 में 60 सीटों पर



चुनाव लड़ेगी, बाकी सभी सीटों पर हमारे सहयोगी दलों के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। यह संकेत दे रहा है कि वीआईपी की महत्वाकांक्षाएँ बढ़ रही हैं।

- *आकांक्षी जिला विकासखण्डों को प्रदाय मेडल सूची में कुआकांडा को मिला कांस्य पदक*
- जिले को यह सम्मान दिलाने में मैदानी कर्मचारियों के अथक प्रयास और समर्पित सेवा भाव अभूतपूर्व-विधायक अटामी शिक्षा, महिला बाल विकास, कृषि और स्वास्थ्य एवं एनआरएलएम के 58 से अधिक कर्मचारियों को किया गया सम्मान



उद्धोधन में मैदानी कर्मचारियों के योगदान को अभूतपूर्व बताते हुए कहा कि उनके अथक प्रयास और समर्पित सेवा भाव से यह उपलब्धि अर्जित हुई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साहू के मंशानुसार पिछड़े जिलों के स्वर्णांगण विकास के लिए संपूर्णता अभियान चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य केन्द्र और राज्य की सभी जनहितकारी योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक षट प्रतिषट पहुँचाना है और हमें प्रसन्नता है कि आज जिला जिन विकास की ऊचाइयों तक पहुँचा है इन्हीं योजनाओं का परिणाम है और इसके लिए सभी विभाग के मैदानी अमले

जनप्रतिनिधि अधिकारी कर्मचारी बर्धाई के पात्र हैं। जिले को आज नीति आयोग की ओर से आकाशी जिला कार्यक्रम के तहत जो सम्मान दिया गया है इस संबंध में हमारा प्रयास रहेगा कि बर्धाई में देवदाज जिले को विकास के आदर्श मॉडल जिला के रूप में स्थापित करेंगे। इस संबंध में उन्होंने जिले में शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य स्वरोज्जागर, पर्यटन संबंधी नवाचारी गतिविधियों का उल्लेख करते हुए कहा कि हम सभी को जिम्मेदारी है कि जिले के विकास में तनमन से अपना योगदान दें। जिला पंचायत अध्यक्ष नरेंद्रलाल मुंडामी ने भी इस सम्मान के लिए अधिकारी कर्मचारी को बर्धाई और

हे प्रशासन उन पर कोई कार्यवाही नहीं करती है, लेकिन प्रदेश सरकार से बड़ा सवाल है? कि कृषि सहकारी समितियों पर रासायनिक उर्वरक उपलब्ध नहीं है परंतु निजी दुकानों पर पर्याप्त मात्रा में डीपीए, यूरिया खाद्य मिल रहे हैं? सरकार जवाब दे बिचौलियों के पास कहा से रासायनिक उर्वरक उपलब्ध हो रहे हैं, शासन - प्रशासन जल्द किसानों के लिए डीपीए यूरिया खाद्य उपलब्ध कराए, ताकि कृषक निजी दुकानों, बिचौलियों के पास रासायनिक उर्वरक लेने के लिए मजबूर न हों। उचित समय पर शासन प्रशासन किसानों के लिए रासायनिक उर्वरक उपलब्ध नहीं करा पाई तो गोंगा प्रदेशव्यापी आंदोलन करेगी। इस दौरान छोटेलाल आयायम ब्लॉक अध्यक्ष प्रतापपुर एवं अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे

जिले के गीदम विकासखण्ड अन्तर्गत ग्राम पंचायत घोटपाल ०१ में बीते गुरुवार को कन्या आश्रम शाला घोटपाल का निरीक्षण किया । बच्चों से चर्चा किया ,साथ ही बच्चों से खाने की गुणवत्ता के बारे में पूछा

छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय जनप्रतिनिधि, बहुप्रशंसित अभिनेता एवं सामाजिक चेतना के सक्रिय हस्ताक्षर धरसीवा विधायक अजय शर्मा को भारतीय प्रबंध संस्थान रायपुर द्वारा आयोजित Gyan Varsha Series में मुख्य वक्ता (Keynote Speaker) के रूप में आमंत्रित किया गया है। यह प्रेरणादायक संगोष्ठी शनिवार, 2 अगस्त 2025 को सायं 3:00 बजे से 4:00 बजे तक, IIM रायपुर परिसर में आयोजित की जाएगी।



अनुभव युवाओं के लिए निःसंदेह प्रेरणादायक होगा। इस कार्यक्रम में दृढ़रूप रायपुर के छात्रगण, प्राध्यापकगण, संस्थान के अधिकारीगण एवं आमंत्रित विशिष्टजन शामिल होंगे। अनुज शर्मा ने इस अवसर को लेकर कहा दृढ़रूप रायपुर जैसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान में युवाओं से संवाद का अवसर पाना मेरे लिए गर्व का विषय है। ज्ञान-वर्षा में भागीदारी के लिए मैं उत्साहित हूँ। यह मंच सिर्फ विचारों का आदान-प्रदान नहीं, बल्कि नेतृत्व की नई दृष्टि गढ़ने की भी माध्यम है। अनुज शर्मा यह भागीदारी न केवल छाँसीसगढ़ की सांस्कृतिक और बौद्धिक परंपरा को राष्ट्रीय पटल पर प्रतिष्ठित करेगी, बल्कि यह कार्यक्रम युवाओं में सामाजिक उत्तरदायित्व, नेतृत्व और मूल्यों के प्रति नवचेतना का संचार करेगा।

जिले के थाना भोपालपटनम क्षेत्रान्तर्गत ग्राम वाडला के ग्रामीणों के लिए एक बड़ी सौगात मिली है। छत्तीसगढ़ शासन की 'निर्दम नेत्र' नार- योजना और केंद्र सरकार की 'यूएसओएफ' योजना के तहत ग्राम वाडला में जिओ का मोबाइल टॉवर प्रारंभ कर दिया गया है। इससे न केवल वाडला बल्कि पोलेम, मटटीमरका, और गोखुर जैसे आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को भी संचार सुविधा का लाभ मिलेगा। संचार व्यवस्था की यह बहाली ग्रामीणों के लिए जीवन में नई ऊर्जा लेकर आई है। बेहतर मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट सुविधा की उपलब्धता से अब ग्रामीण छात्र शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की



मुलस प्रशासन हर हथकडे अपना है वहीं दूसरी ओर अपराधीयो ने मुलसले दिन प्रतिदिन बुतुंद हो रहे हैं की लगातार शिक्का के उपर हत्या जैसे बारदात को अंजाम दे रहे हैं बहरालाल पूरी वाय्य को लेकर बेमतरा गुलिस सतकाल के साथ में कायं करे हैं वहीं पीण्ट पक्ष के लोगों ने मिडिया से चर्चा के दौरान बताया कि अरिखारवा के ही कुछ सरस्यों के साथ में समीन विवाद को लेकर हुआ बुवाई नजदीक ही विवाद हुआ था जिसमें खुला जान से मार देने की धमकी

दिया गया था। शिक्षक की हत्या ग्राम करचुवा खंडेसरा पहुँच मार्ग के बीच दिनदहाड़े चाकू मारकर एक शिक्षक की हत्या कर दिया गया, जो हेमाबंद के शा.हायर सेकेण्डरी स्कूल के टीचर हैं जो ग्राम सुक्की सेन्नी के निवास थे जो वर्तमान में बेमेतरा जिला मुख्यालय में निवासी करते थे। उक्त शिक्षक का नाम सतीश राय है जो बेमेतरा कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने वाले गली में किराए के मकान में रहते थे जो अपने इधुरी से 4 बजे अपने बेमेतरा किराये के निवास आ रहे थे जिनको बीच रोड में रोककर अज्ञात युवकों द्वारा धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दिया वहीं बेमेतरा पुलिस मर्म कायम कर विवेचना कर रही है, समाचार लिखने तक अपराधी की खानबीन जारी रही।

A group of men are seated around a large, light-colored wooden conference table in a meeting room. Some men are wearing face masks. They appear to be in a formal meeting or discussion. The room has large windows in the background.

स्थलों अथवा गोशालाओं में सुसज्जित रूप से रखने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई प्रभुपालक अपने भवेशियों को खुले में छोड़ता है, तो उसके खिलाफ पशु अधिनियमों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय और निर्देश - बैठक में सभी संबंधित विभागों की भागीदारी से समग्र और बहुआयामी कार्ययोजना पर विचार किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर भवेशियों के विचारण को नियंत्रित कर जनसुख्हा, पशु कल्याण, यातायात नियंत्रण, और स्वच्छता को सुनिश्चित करना है। बैठक में लिए गए कुछ प्रमुख निर्णय पशुओं की जड़में नगर निकाय विशेष परियोजना चलकर घुमटू पशुओं को पकड़ें और चिन्हित गोशालाओं अथवा अस्थायी आश्रय स्थलों में सुसज्जित

रूप से विस्थापित करेंगे।

चिन्हित दुष्टता स्थलों पर पुनित गश्त और संसाधनों की निगरानी बढ़ाई जाएगी। जो लोग जानबूझकर अपने पशुओं को खुले में छोड़ते हैं, उनके खिलाफ जुर्माना और अन्य वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। ग्राम सभाओं, स्कूलों, जनचौपाल, रेडियो, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से पशुपालकों को टटल फौंडा, पशु प्रबंधन, और पशु अधिनियमों की जानकारी दी जाएगी।

पशु कल्याण से लेकर सूचना प्रबंधन तक का समावेश - शासन द्वारा तैयार कार्ययोजना में निम्नलिखित प्रमुख बिंदुओं को शामिल किया गया है जिसमें वृद्ध पशुओं और प्रसूतियों, कानी हाथ, गौ-आश्रयण और अस्थायी आश्रयों में विस्थापित किया जाएगा। पूर्व में संचालित गौ-आश्रय स्थलों की स्थायी समितियों को पुनर्जीवित कर संचालन में सहयोग लिया जाएगा। धार्मिक-सामाजिक संगठनों, कॉर्पोरेट्स और एनजीओ के सहयोग से दीर्घकालिक पुनर्वास योजना को कार्यान्वित किया जाएगा।

आवश्यक ससाधन एव सवाए -काउ-कैचर वाहनों की व्यवस्था सभी नगर पालिकाओं, पंचायतों और निकायों के पास सुनिश्चित की जाएगी। चारा प्रबंधन और पशु स्वास्थ्य सेवाओं के

लिए डॉक्टरों की नियुक्ति और अस्पतालों की मैपिंग की जाणी। धायल पशुओं की तत्काल चिकित्सा सुविधा और नियमित स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था होगी। पशुपालकों में जागरूकता एवं सामाजिक सहभागिता ग्राम पंचायत, जनचौपाल, स्कूलों और स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से खुले में पशु छोड़ने के दुष्परिणामों को बताया जाएगा। स्टाएल फीडिंग के लाभ जैसे बेहतर स्वास्थ्य, प्रमल मुखा और दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के बारे में जानकारी दी जाएगी। सोशल मीडिया, रेडियो और टीवी चैनलों के माध्यम से नियमित जागरूकता अभियान चलाया जायेगा।

आपातकालीन और सड़क सुखा उपाय -निर्जित
मार्गों पर संकेतक बोर्ड और स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएंगी।
स्वास्थ्य विभाग, पुलिस और राजस्व विभाग के समन्वय से
दुर्घटना स्थलों पर आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

सूचना प्रबंधन एवं विभागीय जिम्मेदारियों स्पष्ट -एक
केन्द्रीकृत सूचना केंद्र की स्थापना की जाएगी, जो सभी घुमंतु
पत्र घटनाओं, दुर्घटनाओं, और संबंधित सूचनाओं को एकत्रित
कर संबंधित विभागों को तत्काल उपलब्ध कराएगा। इस केंद्र में
टेली प्रिंटर, जियो टैगिंग, और पोर्टल आधारित डैशबोर्ड की
सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

विभागीय जिम्मेदारियों का विभाजन -लोक निर्माण

विभाग सड़क सुरक्षा तत्वों को निर्माण में शामिल करना, ठेकेदारों की जांचबंदीही तय करना। निगरानी दल का गठन, अस्थायी बाड़े का निर्माण, काउन्सैचर वाहन और चारा व्यवस्था। ईयर टैरिंग, पशु चिकित्सा, नस्ल सुधार और गौशाला प्रबंधन। चारागाह प्रबंधन और पशु आहार व्यवस्था। घायल व्यक्तियों के लिए त्वरित चिकित्सा सहायता। चारागाह की उपलब्धता और अवैध कब्जों से मुक्ति। डेटा संकलन और सूचना व्यवस्था। वन क्षेत्रों में आवाप पशुओं को निगरानी और चरागाह प्रबंधन।

प्रशासन को सख्त पदेश : समस्या का स्थायी समाधान अनिवार्य-बैठक के अंत में वरिष्ठ अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि आवाप पशुओं की समस्या अब प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। सदकों की सुरक्षा, नागरिकों का जीवन, और यातायात व्यवस्था की सुचारूत सुनिश्चित करने कार्य करे की मांग है। इस दिशा में सभी विभाग समन्वय से काम करें, यह सुनिश्चित किया गया है। साथ ही सामाजिक सहयोग को भी उत्तम ही अवश्य माना गया है। यह कार्यक्रमों न केवल सड़क दुर्घटनाओं को कम करने में सहायक होगी, बल्कि पशु कल्याण, शहरी व्यवस्था, और स्वच्छता में भी दीर्घकालिक सुधार लाएगी। बेमेतरा जिले की सदकों को ध्यानदारहित, सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए प्रशासनिक अपला और पुनः तहत सफ़िक हो गये हैं।

संपादकीय

हरिद्वार के प्रसिद्ध मनसा देवी मंदिर में एक अफवाह ने कई जातों के लोगों, किसी धार्मिक स्थल पर भगदड़ की यह पहली घटना नहीं, लेकिन अफसोस है कि पुरानी गलतियों से सबक नहीं लिया जा रहा। पिछले एक साल पर नजर दौड़ाएँ तो इस तरह के कई दुखद हादसे हो चुके हैं। पिछले साल जुलाई में ही हाथरस में एक धार्मिक आयोजन में मंची भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई थी। वहां आयोजक भीड़ को

नहीं संभाल पाए। इस साल जनवरी की शुरुआत में तिरुपति मंदिर में टोकन लेने के लिए हद से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच गए और पुलिस उनको काबू नहीं कर सकी। भागदड़ मची तो 6 लोगों की जान चली गई। इसी साल, मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में हुए उसके बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी हादसा हुआ। धार्मिक आयोजनों में भीड़ प्रबंधन हमेशा से बड़ी चुनौती रहा है। अनुमान से ज्यादा लोग जब एक

जगह जुट जाते हैं, तब हल्की-सी भी चूक जानलेवा बन सकती है। इन सारे मामलों में यही वजह रही - कोई अफवाह, भड़क का अनियंत्रित हो जाना और निकलने की जगह न मिलना। किसी भी बड़े आयोजन का सबसे अहम हिस्सा है क्राउड मैनेजमेंट। जरूरी नहीं है कि हड़क के बारे में लगाया गया अनुमान हमेशा सही साबित हो। ऐसे में रियल टाइम मॉनिटरिंग अहम हो जाती है, जिससे स्थिति के

हिंसाब से तुरंत निर्णय लिया जा सके। इस तरह की कोई दुर्घटना होने की सूरत में बचाव की योजना पहले से तैयार रहनी चाहिए। लेकिन, देखा गया है कि ज्यादातर मौकों पर पहले से की गई प्लानिंग बेकार हो गई, क्योंकि इंतजाम नाकामि थे। तमाम धार्मिक स्थलों पर फैली अव्यवस्था को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। फिस्लन भरे रास्ते, सफेदी जगह, आने-जाने का एक ही मार्ग

जैसी बातें लाभांग हर जगह देखने को मिल जाएंगी। ऐसे में जब किसी खास मौके पर भीड़ बढ़ती है तो स्वाभिगत ही हृदय की आशंका भी बढ़ जाती है, जैसा साबित पर मनसा देवी में हुआ। बोलतूरू में आरसीबी के इवेंट में हुए हृदय के बाद कर्नाटक सरकार क्राउड कंट्रोल पर एक बिल लेकर आई है, जिसमें जिम्मेदारियां तय की गई हैं। ऐसे कानून की हर जगह जम्मा है। साथ ही, ऐसी दुर्घटनाओं से बचने के लिए आयोजकों, पुलिस-प्रशासन और जनता को समन्वय में काम करना होगा। बड़े मैदान पर जन-जागरूकता की जरूरत है, जिससे लोगों को बताया जा सके कि भीड़ के बीच उन्हे किस तरह का व्यवहार करना है।

जगदीप धनखड़ 2019 से 2022 तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे। इस दौरान उनका हमेशा सीएम ममता बनर्जी से टकराव बना रहा। धनखड़ ने कई बार सीएम ममता बनर्जी और उनकी सरकार की आलोचना की। धनखड़ ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार और शासन की विफलता के आरोप लगाए। कार्यकाल समाप्ति से दो साल पहले उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने वाले जगदीप धनखड़ का कार्यकाल सर्वाधिक विवादों से भरा रहा है। देश में इतने विवाद उपराष्ट्रपति और राज्यपाल पद पर रहते हुए किसी के साथ नहीं जुड़े, जितने धनखड़ के नाम दर्ज हैं। इस पद पर रहते हुए धनखड़ पर कई तरीके के आरोप लगे। उपराष्ट्रपति पद से पहले पश्चिम बंगाल में राज्यपाल रहते हुए भी धनखड़ विवादों से घिरे रहे। केंद्र की भाजपा सरकार ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ सख्त रवैया अपनाने वाले धनखड़ को ईनाम के तौर पर उपराष्ट्रपति पद से नवाजा था। इसके बावजूद कि धनखड़ का न तो भारतीय जनता पार्टी और न ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से कभी गहरा सरोकार रहा।

सर्वाधिक विवादास्पद राज्यपाल और उपराष्ट्रपति रहे हैं धनखड़

(योगेंद्र योगी)

जनजातीय धनखड़ 2019 से 2022 तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहें। इस दौरान उनका हमेशा सीएम ममता बनर्जी से टकराव बना रहा। धनखड़ ने कई बार सीएम ममता बनर्जी और उनकी सरकार की आलोचना की। धनखड़ ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार और शासन की विफलता पर आरोप लगाए। उनके इस तरह की विषय ने पश्चातापपूर्ण माना, क्योंकि एक संवैधानिक पद पर रहते हुए उनकी टिप्पणियाँ सरकार के खिलाफ थीं। उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के सम्भाषित के रूप में धनखड़ का विषयी दलों के साथ रिश्ता हमेशा तनावपूर्ण रहा। विषय ने उन पर पक्षपात और सरकार के पक्ष में झुलने का आरोप लगाया। राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में धनखड़ पर पक्षपात के आरोप लगे।

विपक्षी इंडिया राष्ट्रबंधन ने आरोप लगाया कि धनखंडू ने राज्यसभा की कार्यवाही में पक्षपात किया और भाजपा सदस्यों को प्राथमिकता दी जबकि विपक्ष की आवाज को दबाया। विपक्ष ने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताते हुए उपराष्ट्रपति पर की गिरफ्तो को ठेस पहुंचाने वाला कदम करार दिया था। देश में ऐसा पहली बार हुआ जब विपक्षी दलों ने राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अधिवास प्रस्ताव पेश किया। हालांकि इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिल सका। विपक्षी दलों में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, समाजवादी पार्टी और वाम दलों के 60 से ज्यादा सांसदों ने सविधान के अनुच्छेद 67 (ब) के तहत धनखंडू के खिलाफ अधिवास प्रस्ताव पेश किया था। प्रस्ताव में उन्हें सकारा का प्रस्ताव कहा गया और निष्पक्षता की गंभीर कमी बताई गई।

जनवरी 2023 में धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट की मूल संरचना सिद्धांत के पुनरावृत्ति के संदर्भ में बयान दिया था, जिसे लेकर विवाद खड़ा हो गया था। उन्होंने कहा था कि संसद के बनाए कानूनों को अगर अदालत रोक देती है तो यह लोकतंत्र के लिए खतरा होगा। विपक्ष ने उपराष्ट्रपति के बयान पर केंद्र सरकार पर हमला बोला। विपक्ष ने इसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप बताया। जस्टिस वर्मा के घर पर कैश ब्यानायक मामले में धनखड़ के बयान के बाद भी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेपीसी) को लेकर बहस छिड़ गई थी धनखड़ ने कहा था कि यदि सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द नहीं किया होता तो बात कुछ अलग होती। गौरतलब है कि एनजेपीसी को सुप्रीम कोर्ट ने हद कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर 2020 दिसंबर में भी धनखड़ ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को यह आदेश संसद की संप्रभुता से समझौता है और जनदेश का अपमान है। मार्च 2023 में धनखड़ ने शैक्षणिक संस्थानों और छात्र

राजनीति पर टटप्पणी की। उन्होंने कहा था कि कुछ विश्वविद्यालय देश विरोधी विचारधाराओं की शरणस्थली बन चुके हैं। उपराष्ट्रपति के इस बयान को जेनयूयू और कुछ अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों की ओर इशारा माना गया। विपक्षी दल, जैसे सीपीआई और सीपीएम ने उपराष्ट्रपति के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उपराष्ट्रपति की यह भाषा सीपी एजेंडे की झलक देती है। छत्र संभालने से धनखड़ से बयान वापस लेने की मांग की थी। किसान आंदोलन के दौरान जायदूध धनखड़ ने किसानों की आलोचना की। उन्होंने कहा था कि किसान आंदोलन के नाम पर सड़कों पर बैठ कर राह को बदनाम कर रहे हैं, वे किसान नहीं हैं। धनखड़ की इस टिप्पणी पर किसान संगठनों और खाप संगठनों ने आपत्ति जताई। अक्टूबर 2024 में उन्होंने सीबीआई और ईडी के समर्थन में बयान दिया था। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा था कि, सीबीआई और ईडी पर सवाल उठाना भारत के न्यायिक तंत्र को कमजोर करता है। उनके इस बयान को विपक्षी दलों ने जांच एजेंसियों की मनमानी कार्रवाई का समर्थन के तौर पर माना।

कांग्रेस सांसद जयराम रमेश द्वारा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव 27 मार्च 2025 को लाया गया। इस विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव को धनखंड ने खारिज कर दिया। अमित शाह ने आरोप लगाया था कि यूपीए शासनकाल में पीएमएनआरएफ (प्रधानमंत्री

राष्ट्रीय रहत कोष) पर सोनिया गांधी का नियंत्रण है। धन्यवाद ने एक प्रेस विज्ञप्ति का हवाला देते हुए इसे सत्यापित बयान बताया। अगस्त 2024 में महिला गरिमा पर बहस के दौरान राज्यसभा में समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने धनखड़ कोष की बोलने की शैली और हाव-भाव पर आपत्ति जताई। बच्चन ने कहा कि उनकी ओर अनुचित है। इसके जवाब में धनखड़ ने कहा कि आप सचिलिब्री हो सकते हैं लेकिन सदन की मर्यादा समझिए।

दिसंबर 2023 में उपराष्ट्रपति धनखड़ पर अधिवेशन में विपक्षी दलों को रोकने का आरोप लगा था। विपक्षी सत्तों के नेताओं ने आरोप लगाया कि संसद के शीत सत्र में विपक्षी सांसदों के साथ प्रक्षपात किया जा रहा है। विपक्ष अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे ने कहा था कि यह उपराष्ट्रपति नहीं, भाजपा प्रवक्ता की तरह बर्ताव कर रहे हैं। सभापति धनखड़ की संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन की कार्यवाही का संचालन करते हुए लोकतंत्र को खरबा वाला बयान दिया। जिसे लेकर जमकर विवाद खड़ा हुआ। उन्होंने कहा था कि कुछ लोग लोकतंत्र को खत्म करने में लगे हैं और उन्हें संसद में नहीं देशद्रोहियों के कटघरे में होना चाहिए। उपराष्ट्रपति धनखड़ का यह बयान इशारे के तौर पर विपक्ष की संसद में बहिष्कार रणनीति के संदर्भ में दिया गया।

कई विपक्षी नेताओं ने असहमति जताते हुए कहा था कि यह लोकतंत्र में असहमति को दबाने की कोशिश है। धनखड़ अपने कार्यकाल के दौरान संवैधानिक

संस्थानों और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर अपनी टिप्पणियों के लिए भी चर्चा में रहे। उन्होंने आरएसएस को वैश्विक धार्मिक ढँक और राष्ट्र निर्माण में निर्विवाद भूमिका वाला संगठन बताया, जिसे विपक्ष ने भाजपा के प्रति उन्मील नज़र के रूप में बताया। राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा चुनाव के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ की बार-बार राजस्थान दौरे को लेकर आपत्ति जताई थी। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा था कि शेखावत साबिक भी उपराष्ट्रपति बने थे। लेकिन उन्होंने कहा था कि राजस्थान मेरा घर है। यहाँ कोई प्रोटोकॉल नहीं होगा। जबकि उपराष्ट्रपति धनखड़ पूर्व प्रोटोकॉल के तहत राजस्थान के दौरे पर आ रहे हैं।

गहलोत ने उपराष्ट्रपति धनखड़ पर तंज कसते हुए कहा था कि आप उपराष्ट्रपति हैं। आपका स्वागत है। लेकिन इनके इस तरीके से बार-बार राजस्थान में अपना दौरा करती तो, जनता तो सब समझती है। इस दौर को करने की क्या तुक हैं। जनता समझती है। राजस्थान में चुनवा है, इसलिए उपराष्ट्रपति भी सक्रिय हैं। संविधान में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल जैसे संवैधानिक पदों के लिए विशेष प्रावधान और सम्मान है। सवाल यह है कि इन प्रावधानों और सम्मान के विपरीत पदों को विवादित बनाने से इन पदों की गरिमा कैसे बनी रहेगी, यह इन पदों पर आसीन लोगों के विचारणीय प्रश्न है। (इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

कार्डे से आयेक को किससे पारोयोजना को उद्धान भी कर रहे हैं। इससे यह संशय जाता है कि सांस्कृतिक गौरव और आर्थिक प्रगति एक-दूसरे के पूरक हैं। भाजपा इस संतुलन को दिखाकर तिलनाडु की जनता को यह विश्वास दिलाना चाहती है कि केंद्र सरकार क्षेत्रीय विकास और सांस्कृतिक सम्मान दोनों पर ध्यान दे रही है। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री गैंगोक्षचोलपुरम में सम्राट राजेन्द्र चोल प्रथम की जयंती मनावे और आदि तिरुवाथिरै महात्म्य में शामिल होने के साथ ही राजेन्द्र चोल प्रथम एक स्मारक सिक्का जारी करेंगे। यह सम्राट चोल साम्राज्य की समुद्री विजय के 1000 वर्ष पूरे होने और गैंगोक्षचोलपुरम मंदिर के निर्माण की स्मृति में आयोजित हो रहा है।

जहाँ तक यह सवाल है कि क्यों डीएमके और भाजपा चोल सम्राट राजेन्द्र प्रथम को लेकर राजने-सामने हैं तो आपको बता दें कि भारतिय आजीने-सामने हैं इतिहास और प्रतीकों का इस्तेमाल नया नहीं है। लेकिन यहां असली सवाल यह है कि आखिर एक हजार वर्ष पूर्व के इस महान चोल सम्राट के नाम और योगदान को लेकर इतनी खींचतान क्यों? सवाल यह भी है कि इसके राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक मायने क्या हैं? हम आपको बता दें कि राजेन्द्र प्रथम चोल साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली शासकों में गिने जाते हैं। राजेन्द्र प्रथम (1014-1044

इ.) को दक्षिण भारत का सबसे महान समुद्री विजेता माना जाता है। उन्होंने श्रीलंका, मालदीव, अरु (म्यांमार), थाईलैंड और कंबोडिया तक अपना प्रभाव बढ़ाया। गंगा जल लेकर चोल राजधानी में अभिषेक करने वाली उनकी उपलब्धि उन्हें गंगैकोड चोल की उपाधि दिलाती है। उनके शासनकाल में प्रशासनिक, सांस्कृतिक और समुद्री व्यापारिक नेटवर्क का जबर्दस्त विस्तार हुआ। इसके अलावा, राजेन्द्र प्रथम केवल सैन्य शक्ति का प्रतीक नहीं थे, बल्कि सांस्कृतिक और स्थापत्य कला के भी बड़े संरक्षक थे। तंजावुर और गंगैकोड चोलपुरम के भव्य मंदिर उनकी धार्मिक सहिष्णुता और स्थापत्य कौशल को दर्शाते हैं। गंगैकोडचोलपुरम मंदिर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और तमिल शैव भक्ति परंपरा का महत्वपूर्ण केंद्र है।

देखा जाये तो डीएमके के लिए राजेन्द्र प्रथम तमिल गौरव और द्रविड़ संस्कृतिक के प्रतीक है। पार्टी लंबे समय से यह हार्क देने रही है कि तमिल सभ्यता का इतिहास बेहद समृद्ध है और इसे उरिया भारत के इतिहास ऐतिहासिक आख्यानों में दबा दिया गया। छुछ चाहती है कि तमिल लोगों को यह एहसास हो कि उनके पूर्वजों ने समुद्र पार साम्राज्य खड़ा किया था। इसके अलावा छुछ इस विषय को ब्राह्मणवादों इतिहास लेखन के प्रतिरोध के रूप में भी प्रस्तुत करती है। द्रविड़ आंदोलन के सामाजिक न्याय और जातिगत असमानताओं को चुनौती देने के एजेंडे के साथ, राजेन्द्र प्रथम का तमिल गौरव पार्टी के राजनीतिक विपक्षों में मजबूती से फिट बैठता है।

दूसरी ओर, भाजपा की रणनीति थोड़ी अलग है। पार्टी रानन्द प्रथम को 'हिंदू साम्राज्यवाद शक्ति' के रूप में प्रस्तुत कर रही है, जिसने विदेशी ताकतों को परास्त कर भारत की सीमाओं के बाहर भी हिंदू प्रभाव फैलाया। यह नैरेटिव बीजेपी की व्यापक 'सांस्कृतिक रणवाद्' की सोच से जुड़ा है। इसके अलावा भाजपा तमिलनाडु में अपनी जड़ें मजबूत करना चाहती है, जहां अब तक उसकी उपस्थिति सीमित रही है। डीएमके के तमिल गौख को चुनौती देने के लिए बीजेपी ऐतिहासिक नायकों को हिंदुत्व के चरम से प्रस्तुत कर रही है। इससे उसे तमिलनाडु में सांस्कृतिक जुड़ाव बनाने का अवसर मिलता है दोनों दलों को खींचतान में निहितार्थ पर गौर करें तो डीएमके तमिल पहचान और द्रविड़ गौरव पर जोर देती है, जबकि भाजपा हिंदू पहचान और राष्ट्रीय गौरव पर। इसके अलावा, यह लड़ाई केवल अतीत की स्मृतियों की नहीं, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए इतिहास को परिभाषित करने की भी है। यह भी देखने में आ रहा है कि भाजपा दक्षिण भारत में पैर जमाने के लिए क्षेत्रीय प्रतीकों को अपनाने की रणनीति पर काम कर रही है, जबकि डीएमके इस क्षेत्रीय अस्मिता को बचाने की कोशिश में है।

चोल सम्राट राजेन्द्र प्रथम को विरासत पर चल रही यह खींचतान बताती है कि इतिहास केवल अतीत का विषय नहीं है, बल्कि वर्तमान को राजनीति का हथियार बन जाता है। डीएमके और भाजपा दोनों ही राजेन्द्र प्रथम को अपने-अपने वैचारिक ढांचे में फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। यह संघर्ष आने वाले समय में तमिलनाडु की राजनीति को और अधिक वैचारिक और सांस्कृतिक बहसों से भर देगा।

बहरहाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तूतीकोरिन से गैंगौंडाचोलपुरम तक का यह दौरा विकास और सांस्कृतिक प्रतीकवाद का एक संतुलित उदाहरण है।

वर्तमान युग में औद्योगीकरण, अंधाधुंध शहरीकरण, वनों की कटाई, जल और वायु प्रदूषण, प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग और जलवायु परिवर्तन ने प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ दिया है। हर साल लाखों एकड़ वन समाप्त हो जाते हैं, सैकड़ों प्रजातियाँ विलुप्त हो जाती हैं और प्राकृतिक आपदाएँ लगातार बढ़ रही हैं। हर वर्ष 28 जुलाई को मनाया जाने वाला विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस हमें प्रकृति, पर्यावरण एवं सृष्टि के संतुलन एवं संरक्षण के लिये प्रेरित करता है। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के महत्व को उजागर करते हुए यह दिन हमें प्रकृति के साथ अपने संबंधों पर विचार करने और एक स्थायी भविष्य की दिशा में कदम उठाने का आग्रह करता है।

(ललित गर्ग)

यह इस बात को मान्यता देता है कि एक स्वस्थ एवं संतुलित समाज की नींव ही एक स्वस्थ पार्यवर्णन है। हम जानते हैं कि केवल उपयोगकर्ता नहीं, बल्कि उसके संसंधक भी हैं। इस दिवस की वर्ष 2025 की थीम-प्रकृति के साथ सामंजस्य पुनर्स्थापित करें, पुनर्जीवित करें, पुनःकल्पना करें है जो न केवल हमारे पार्यवर्णीय कर्तव्यों को रेखांकित करती है, बल्कि यह एक गंभीर चेतावनी भी है कि यदि हम अब भी नहीं जागे, तो प्रकृति हमें अपने ढंग से जगाएगी और पुनर्जिव्य जगणन महंगा पड़ सकता है। थीम के अनुसार 'पुनर्स्थापित' करना यानी प्रकृति को उसकी मूल अवस्था में लाना, 'पुनर्जीवित' यानी मृत या निष्क्रिय हो चुकी प्राकृतिक प्रणालियों को पुनर्जीवित करना और 'पुनःकल्पना' यानी एक ऐसे भविष्य की कल्पना करना जो सतत विकास, हरित ऊर्जा और मानव-प्रकृति सह-अस्तित्व पर आधारित है। इस थीम का सार यह है कि हम केवल 'मदद' नहीं कर रहे, बल्कि प्रकृति के प्रति अपने दायित्वों को निभा रहे हैं, ज्योंकि हमारी जीवनीशैली ही प्राकृतिक संसाधनों की सबसे बड़ी उपभोक्ता है।

वर्तमान युग में औद्योगीकरण, अंधाधुंध शहरीकरण, अत्यधिक की कटाई, जल और वायु प्रदूषण, प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग और जलवायु परिवर्तन ने प्रकृतिक वनस्पतिलुन को बिगाड़ दिया है। हर साल लाखों एकड़ वन समाप्त हो रहे हैं, जैसे-जैसे, संस्कृत प्रजातियाँ विलुप्त हो जाती हैं और प्राकृतिक नगार बढ़ रही हैं। यह स्थिति न केवल जैव विविधता को नष्ट कर रही है, बल्कि मानव अस्तित्व पर भी सीधा खतरा बन चुकी है। भारत की प्रकृति चुनौतियाँ गंभीरतापूर्वक हैं, एक पक्ष से, एक संकट है, लगातार है जैसे कुछ अधूरा है, एक पक्ष से, एक संकट है, लगातार है जैसे कुछ अधूरा है, एक पक्ष से, एक संकट है, लगातार है जैसे कुछ अधूरा है।

२०००वीं संसदीय रिपोर्ट बताती है कि भारत में करोड़ों लोग अभी भी स्वच्छ जल से वंचित हैं। सयानयनयन कृषि, प्लास्टिक प्रदूषण, मार्निंग प्रेतित जल प्रदूषण-इन्से नदियां, तालाब, भूजल, प्रकृति सभी दूषित हो रहे हैं। सतत जल सुरूक्षा का अर्थ है हर परिवार को शुद्ध, पर्याप्त और स्वस्थ सभी मिलना चाहिए। शुद्ध हवा व शुद्ध जल कैसर, हृदय-पक्षाघात, सांक्रामिक और पुरानी बीमारियों को रोकते हैं। स्वस्थ जीवनशैली और निरोगी समाज अत्यवस्था के लिए पड़ा है। जीवन के तीन आधार तथ्य हैं-हवा, पानी और भोजन है। प्रकृति संरक्षण न केवल हमारी अस्तित्व-निर्भरता से जुड़ी है, बल्कि मानवता की नैतिक जिम्मेदारी भी है। आज का युग, जिस तेजी से विकास हो रहा है, उसी भागदौड़ में प्रकृति पर तरह-तरह के आघात हो रहे हैं। रूस-यूक्रेन युद्ध, हमाम-इजरायल युद्ध, थाईलैंड- कंबोडिया युद्ध, दक्षिण का उच्च प्रदूषण सूचकांक, अमेरिका के जंगलों की धुएं से गंदली हवा, बढ़ता वाहन प्रदूषण-ये सब प्रकृति देते हैं कि प्रकृति रक्षित हो रही है, कदन कर रही है।

भारत एक समृद्ध जल-विविधता वाला देश है, लेकिन यहाँ भी वनों की कटाई, नदियों का प्रदूषण, और ग्लेशियरों का पिघलना चिंताजनक स्तर पर पहुँच चुका है। हाल ही में उत्तराखंड, हिमाचल और पूर्वोत्तर राज्यों में आई जलवायु अपवाद स्पष्ट संकेत हैं कि प्रकृति अब चेतावनी दे रही है। पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारों या संगठनों की जिम्मेदारी नहीं, हर नागरिक का कर्तव्य है। हमें यह समझना होगा कि प्रकृति की रक्षा करके हम वास्तव में अपने भविष्य की रक्षा कर रहे हैं। प्रकृति संरक्षण की दिशा में कदम बढ़ाते हुए हमें सतत विकास को प्राथमिकता देनी होगी, जिसमें पर्यावरण, समाज और आर्थिकवस्था में संतुलन बना रहे। पुनःवनीकरण और वृक्षारोपण को एक राष्ट्रीय अभियान बनाना होगा। सिंगल यूज प्लास्टिक को समाप्त करने के लिए सख्त कदम उठाने होंगे। स्थानीय परिस्थितिक तंत्रों की सुरक्षा—जैसे जल स्रोत,

जैव विविधता, मिट्टी की उर्वरता, हरित ऊर्जा- जैसे सौर और पवन ऊर्जा को प्रोत्साहन देना होगा। बच्चों और युवाओं में पर्यावरणीय चेतना विकसित करनी होगी।

प्रकृति एवं पर्यावरण की उपेक्षा के कारण विकास सबद नही अभिगाथा बन रहा है। वायु प्रदूषण जानलेवा विकार हो रहा है, गंगा-यमुना प्रदूषित हो चुकी है, जना को पीने का शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है, सड़के गड्डों में तब्दील हो चुकी है। वनों का विनाश हो रहा है, पहाड़ बिखर रहे हैं, जहरीली हवा एवं वायु प्रदूषण से उत्पन्न दमघोड़ माहौल का संकेत जीवन का संकट बनने लगा है। और जहरीली होती हवा सांसों पर भारी पड़ने लगी है। एयर क्राइटी इंडेक्स यानी एअरुआइ बहुत खराब की श्रेणी में पहुँच चुका है। दिल्ली के सास देश के अल्प महानगरीय की आबोहवा भी बच्चों और बुजुर्गों के लिए विशेष रूप से खतरनाक है। महानगरीयों की हवा में उच्च सांद्रता है, जो बच्चों को सांस की बीमारी और हृदय रोगों की तरफ धक्का रखी है। शोध एवं अध्ययन में यह भी पाया गया है कि यहां रहे वाले 75.4 फीसदी बच्चों को घुटन महसूस होती है। 24.1 फीसदी बच्चों की आंखों में खुजली की शिकायत होती है। सर्दियों में बच्चों को खासी की शिकायत भी होती है। बुजुर्गों का स्वास्थ्य भी बढ़ते ज्यादा प्रभावित होता है। सर्दियों के मौसम में हवा में घातक धातुएं होती हैं, जिससे सांस लेने में दिक्कत आती है। हवा में केडियम और अर्चनिक की मात्रा में वृद्धि से कैंसर, गुर्दे की समस्या और उत्पन्न रक्तचाप, मधुमेह और हृदय रोगों का खतरा बढ़ जाता है।

दुनिया भर में 2.2 बिलियन लोगों के पास सुशुद्धित रूप से प्रबंधित पेयजल तक पहुंच नहीं है। आज जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियर पहले से कहीं अधिक तेजी से पिघल रहे हैं। अबों लोगों के लिए पिघले पानी का प्रवाह बदल रहा है, जिससे बाढ़, सूखा, भूस्खलन और समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है। अनगिनत भूमदायु और पारिस्थितिकी

तंत्र विनाश के खतरे में हैं। कार्बन उत्सर्जन में वैश्विक कटौती तथा सिक्कुडो ग्लेशियरों में अनुत्पन्न के लिए स्थानीय रणनीतियाँ आवश्यक हैं। दुनिया की आबादी अठारह स अर्ध को बढ़ा चुकी है। इसमें से लगभग आधे लोगों को साल में कम से कम एक महीने पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ता है। जलवायु परिवर्तन के कारण 2000 से बाढ़ की घटनाओं में 13.4 प्रतिशत वृद्धि हुई है और सूखे की अवधि में 29 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। पैकेट और बोतल बंद पानी आज विकास के प्रतीक चिह्न बनते जा रहे हैं और अपने संसाधनों के प्रति हमारी लापरवाही अपनी मूलभूत आवश्यकता को बाजारवाद के हवाले कर देने की राह आस कर रही है।

व्यक्तिगत पहल के रूप में प्रकृति के प्रति हम को दशति हुरु जितना हो सके, प्राकृतिक संसाधनों का संयमित उपयोग करें। अपरिहार प्रबंधन, पुनः उपयोग, और रसायनिकों का अपनाना। प्रत्येक वर्ष कम से कम एक वृक्ष लगाएं और उसका पालन करें। जल, वायु और ध्वनि प्रदूषण को कम करने की कोशिश करें। प्रकृति के प्रति एक सज्जन, सज्जनशिल और समर्पित दृष्टिकोण अपनाना। वर्ष 2025 का यह विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस हमें प्रकृति से नया रिश्ता बनाने का अवसर देता है, एक ऐसा रिश्ता जिम्में हम उपयोगकर्ता नहीं, बल्कि संरक्षक और सहजगीर बनें। यदि हम प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं, तो प्रकृति भी हमें जीवन, स्वास्थ्य, और समृद्धि प्रदान करेगी। प्रकृति हमारी माँ है, हम उसका अपमान नहीं, सम्मान करें; उसके घावों को और न बढ़ाएं, अब उस महान् देवता से। अब समय है पुनर्संपन्न, पुनर्जीवन और पुनःकल्पना के मंत्र को अपने जीवन में उतारने का, ताकि एक हरित, सुरक्षित और सुंदर पृथ्वी आने वाली पीढ़ियों को विरासत में दी जा सके। इसके लिये हर राजनीतिक दल एवं सरकारों को संवेदनशील एवं अन्तर्दृष्टि-सम्पन्न बनना होगा। लेखक, पत्रकार, स्तंभकार है।

उन्के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। यह कार्यक्रम केवल बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, बल्कि समाज में महिला सशक्तिकरण की भावना को भी मजबूती प्रदान करता है। महिला एवं बाल विकास विभाग की यह पहल आने वाले समय में एक सकारात्मक बदलाव की आधारशिला बनेगी।

